vinetur

भारत और यूरोपीय संघ 16 दिसंबर को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं

दो दशक से अधिक की बातचीत के बाद समझौते से भारतीय खेपों के 93% को यूरोपीय संघ में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी

सोमवार, 23 नवंबर 2026



प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के हवाले से एक अधिकारी के अनुसार, भारत और यूरोपीय संघ 16 दिसंबर को ब्रसेल्स में लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इससे दो दशक से अधिक की बातचीत के बाद भारत और 27 सदस्यीय संघ के बीच व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा पड़ाव स्थापित होगा।

दोनों पक्षों ने 27 जनवरी को बातचीत पूरी की थी। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत Jean-Eric Paquet ने कहा है कि दिसंबर में प्रधानमंत्री Narendra Modi की ब्रसेल्स यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। Paquet ने यह भी कहा है कि समझौता 2027 में लागू होने की संभावना है।

यूरोपीय आयोग ने समझौते पर हस्ताक्षर और उसे अंतिम रूप देने की अनुमति मांगने वाले प्रस्ताव, अंतिम कानूनी

मसौदे और शुल्क-सूचियों के साथ, यूरोपीय संघ की परिषद को भेज दिए हैं। यह कदम दर्शाता है कि प्रस्तावित हस्ताक्षर की तारीख से पहले समझौता यूरोपीय संघ की औपचारिक मंजूरी प्रक्रिया से आगे बढ़ रहा है।

PTI के हवाले से अधिकारी के अनुसार, समझौते के तहत भारतीय खेपों के 93% को यूरोपीय संघ में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे भारतीय निर्यातकों को दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक तक अधिक व्यापक पहुंच मिलेगी और उन क्षेत्रों को मदद मिल सकती है जो सीमा पर कम लागत और बाजार में प्रवेश के अधिक अनुमानित नियमों पर निर्भर हैं।

इस समझौते से यूरोप से भारत आने वाले कुछ आयातों की लागत भी घटेगी, जिनमें लग्जरी कारें और वाइन शामिल हैं। पेय कारोबार के लिए, यूरोपीय वाइन पर कम शुल्क से भारतीय बाजार तक पहुंच बेहतर हो सकती है। इससे आयातक, वितरक और निर्यातक 2027 में समझौते के संभावित लागू होने से पहले कीमतों, उत्पादों के मिश्रण और शिपमेंट की योजनाओं पर फिर से विचार कर सकते हैं। व्यावसायिक असर अंतिम शुल्क-सूचियों और इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां नई शर्तों का लाभ उठाने के लिए कितनी तेजी से कदम उठाती हैं।

यह समझौता दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आर्थिक समूह यूरोपीय संघ से जोड़ेगा और लगभग 2 अरब लोगों का बाजार बनाएगा। PTI की रिपोर्ट में उद्धृत आंकड़ों के मुताबिक, भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 25% और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं। यह व्यापार वैश्विक कुल लगभग $33 ट्रिलियन में से करीब $11 ट्रिलियन है।

दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक संबंध पहले से ही महत्वपूर्ण हैं। यूरोपीय संघ अलग-अलग आर्थिक समूहों में भारत का वस्तुओं का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि वैश्विक स्तर पर भारत यूरोपीय संघ का वस्तुओं के व्यापार में नौवां और सेवाओं में छठा सबसे बड़ा भागीदार है। समझौते के पूरा होने से शुल्क घटाकर, व्यापारिक बाधाएं कम करके और बाजार तक पहुंच के स्पष्ट नियम देकर ये संबंध और गहरे हो सकते हैं।

प्रस्तावित हस्ताक्षर बातचीत में वर्षों की धीमी प्रगति के बाद एक उल्लेखनीय राजनीतिक और आर्थिक कदम होगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार वार्ता दो दशक से अधिक समय तक चली। दोनों पक्षों ने 27 जनवरी को नवीनतम दौर पूरा किया, जिससे अधिकारियों के लिए बातचीत से आगे बढ़कर कानूनी और प्रक्रियागत मंजूरी की दिशा में काम करना संभव हुआ।

अंतिम नतीजा अभी भी यूरोपीय संघ की प्रक्रिया के बाकी औपचारिक चरणों और 16 दिसंबर को ब्रसेल्स में होने वाले आधिकारिक हस्ताक्षर पर निर्भर है। यदि यह समय-सीमा कायम रहती है, तो विनिर्माण, कृषि, सेवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं के कारोबार से जुड़ी कंपनियां दुनिया के दो सबसे बड़े बाजारों के बीच नए व्यापार ढांचे की तैयारी शुरू करेंगी। इनमें वाइन कारोबार भी शामिल है, जो शुल्क में बदलाव पर करीबी नजर रखेगा।